श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं झारखंड के कोयला अंचल से आता हूं, जहां कोल और मिनरल की माइनिंग की जाती है। रात-दिन माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के प्रौसेस में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि लोग मर रहे हैं।

श्री सभापतिः सवाल पूछिए।

श्री संजीव कुमार : सर, एक सैकिंड।

श्री सभापतिः नहीं, मुझे आलाप की जरूरत नहीं है।

श्री संजीव कुमार : सर, उस क्षेत्र में जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, वे सब पॉल्यूट हो चुके हैं, जिसके कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से सीधे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि 'निर्मल भारत अभियान' को 'ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन' में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इस मिशन के तहत क्या आप कोयलांचल में पीने के पानी की व्यवस्था पाइप लाइन के जरिए कर रहे हैं या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please be brief with the answer.

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः माननीय सभापति महोदय, ब्रीफ में तो यह है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह ड्रिंकिंग वाटर का सवाल पूछ रहे हैं और यह सवाल सैनीटेशन का है। इससे ब्रीफ तो और कोई हो नहीं सकता।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Dr. Anil Kumar Sahani.

डॉ. अनिल कुमार साहनीः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि 'निर्मल भारत अभियान' के अन्तर्गत आपने दिनांक 1.4.2012 से 1-10-2014 तक चले कार्यक्रमों को बन्द किया, तो क्या इतने दिनों में झारखंड और झारखंड के सभी स्कूल और आंगनवाड़ियों में शौचालयों की व्यवस्था हो चुकी है और जो आप नया अभियान चलाने जा रहे हैं, उसके अनुसार वहां कब तक शौचालयों की स्थापना होगी और स्वच्छता आएगी और वह क्षेत्र कब तक निर्मल होगा?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः सर, झारखंड के स्कूलों में टॉयलेट्स यानी शौचालयों की बात पूछी गई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 में 1228 स्कूलों को यह सुविधा दी गई, वर्ष 2012-13 में 613 स्कूलों में शौचालय बनाए गए और वर्ष 2013-14 में 682 एवं वर्ष 2014-15 में दिनांक 12 मार्च, 2015 तक 1361 स्कूलों में शौचालय बनाए गए।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question 183.

Coverage of Indira Awaas Yojana

*183. SHRI ANUBHAV MOHANTY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of people benefited under Indira Awaas Yojana (IAY);

(b) the number of houses sanctioned to the beneficiaries thereunder in Odisha; and

(c) whether there is any proposal to increase the quota for that State?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Indira Awaas Yojana (IAY) is a continuous and an ongoing allocation based Scheme and is implemented by all States and UTs except Delhi and Chandigarh. Under the Scheme, financial assistance is provided to the rural BPL families for construction of houses. 73.47 lakh people have been benefited under IAY during the last three years including current year so far.

(b) 3.87 lakh houses were sanctioned under IAY during the last three years including current year in Odisha

(c) At present there is no proposal to increase the quota for the State in the next financial year.

MR. CHAIRMAN: Supplementaries, please.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: I beg your pardon, Sir. I am quite nervous. It is for the first time that I am putting a question in this House.

Through you, Sir, I would like to put a question to the hon. Minister. Out of a total sanction of ₹ 842 crores in the financial year 2014-15, my State, Odisha, has received only ₹ 565 crores. The proposal for the second installment has already been provided. Yet, we haven't received it. So, I would like to ask by when the rest of the amount will be received by Odisha so that this programme continues without any delay.

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह : सर, इंदिरा आवास योजना का ओडिशा स्टेट का इस साल का जो लक्ष्य था, यह तय हुआ था कि तीन साल के अंदर 3 लाख 87 हज़ार घरों को अनुदान दिया जाएगा और उसके लिए जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जो अमाउंट सेंक्शन किया था, वे यह कह रहे हैं कि वह पूरा नहीं आया। बहुत सी ऐसी प्रोसीजरल चीज़ें हैं, जैसे कि यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट है.. और दूसरे, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंदिरा आवास योजना का पैसा सिर्फ स्टेट को नहीं जाता। स्टेट से वह डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है और कई डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कई डिस्ट्रिक्ट्स उसमें बहुत पीछे होते हैं, तो उनका जो unspent पैसा है, हमने अब ऐसी गाइडलाइन्स जारी की हैं कि उस unspent पैसे का इस्तेमाल दूसरे जिस जिले में, जिसने अच्छा काम किया है, वहां उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें अगर टार्गेट पूरा होगा, क्योंकि इसमें सारे का सारा जो टार्गेट निर्धारित है, हम यह चाहते हैं कि एक स्टेज पर तो इनका जो टार्गेट था, वह 2014-15 में 1 लाख 61 हज़ार था और अभी तक सिर्फ 7 हज़ार हाउसेज़ की रिपोर्ट हमारे पास

आई है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर दूसरे ज़िलों से भी रिपोर्ट आएगी, तो पैसा रिलीज़ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: Now, the second question.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I will certainly see to it that the rest of the requirement will be provided to them very soon by the Central Government. But, I believe but anyway, Sir, I am from Odisha and we have 31 lakh Kutcha houses. We are really unfortunate that we have a huge volume of Kutcha houses in Odisha and for this reason the hon. Chief Minister had requested in the last meeting of the NITI Aayog that, at least, five lakh Kutcha houses to be sanctioned for this coming year 2015-16. But in the last three years, only 3.87 lakh houses were sanctioned. Sir, when there is a huge demand of 31 lakh Kutcha houses and in the last three years, only 3.87 lakh houses were sanctioned, how is it possible to provide good houses to the poor to stay. How these poor people are going to face the reality? So, I request the Minister to please answer this.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, this question is not relating to Odisha only. There are about two crore ninety five lakh families which are deprived of this; they are not having any shelter. So, we have moved the Finance Department regarding this. We have constructed 73 lakh houses during the last three years. For the remaining we have moved the Centre for extra funds and the Prime Minister is also very much concerned of this that by 2022, there should not be any family which is without shelter. So, it is a huge programme and it requires not in thousands but in lakhs of crores of rupees. But, as far as Odisha is concerned, we have placed at their disposal ₹ 2,623 crores in the last three years and utilization has been only ₹ 2,185 crores. So, that means for the target which they fixed, they have the amount with the respective districts. As I have already said in my first reply, there is no dearth of funds so far as Odisha is concerned.

SHRI RANJIB BISWAL: Mr. Chairman, Sir, due to widespread corruption and irregularities, the Indira Awas Yojana in Jagatsinghpur district of Odisha has been suspended for two years now. I would like to know whether the Minister is aware of it. Has the probe begun? What measures has the hon. Minister taken to help the beneficiaries?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Mr. Chairman, Sir, the funding pattern is such that we provide 75 per cent amount and the rest of the amount is provided by the State Government.

Implementation, by and large, is the responsibility of the State. Still, whenever

we get any such information where funds are not being utilized properly or there has been something wrong with utilization of funds or some corruption element is there, then....

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I have asked about the Indira Awas Yojana being suspended. Is the Minister aware of it?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, so far as this district is concerned, I do not have any information. I would still say that if there is any such information available with the hon. Member, we would certainly ask the State Government to go into it.

श्री भूपिंदर सिंह : सर, राज्य सभा के सभी मेंबर्स इस बात पर एकमत होंगे कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर बनाने के लिए जो धनराशि देने की बात की जा रही है, उसके अतंर्गत घर बनाने के लिए जो रेट्स फिक्स किए गए हैं, 75,000 for normal area and 90,000 for hilly area, वे बहुत कम हैं— इस बात को सारा हाउस महसूस कर रहा है। क्या सरकार इस पर गौर करेगी और 1,50,000 रुपए तक इसकी वृद्धि करेगी? इसके अतिरिक्त जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में फेलिन के चलते ओडिशा में 1 लाख 9 हजार घर उजड़ गए, उनके लिए इंदिरा आवास योजना में क्या आप कुछ स्पैशल सैंक्शन करेंगे?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह : सभापति जी, मैंने पहले भी बताया कि यह अमाउंट पहले सिर्फ 40,000 रुपए होता था। अभी पिछले साल ही इसको 40,000 से बढ़ाकर 70,000 किया गया तथा जो डिफिकल्ट एरियाज़ हैं, उनमें इसको 75,000 रुपए तक किया गया। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि न 70,000 से कोई अच्छा मकान बन सकता है और न ही 75,000 से। सही मायनों में हमने यह प्रपोज़ल दिया है कि कम से कम 1 लाख 15 हजार रुपया दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो उसका प्लॉट है, उसका साइज़ भी हमने 25 स्क्वेयर मीटर करने का फैसला लिया है क्योंकि 25 स्क्वेयर मीटर अगर प्लॉट होगा तो कम से कम, जिसको हम घर कह सकते हैं, सिर्फ कमरा या रूम नहीं, बल्कि घर कहने लायक वह बन सकता है। जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम को हमने वित्त मंत्रालय को भेजा हुआ है। ज्यों ही इस पर कोई स्वीकृति आएगी, हम हाउस को इसकी सूचना जरूर देंगे।

श्री भूपिंदर सिंह : 1 लाख 25 हजार में बिल्कुल नहीं बनेगा।

श्री दिलीप कुमार तिर्की : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का इंदिरा आवास योजना, 2014-15 का जो प्रपोज़ल है, उसके लिए जो भी फंड है, क्या उसे आप बिना कटौती किए देने का प्रयास करेंगे?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह : क्या आप ओडिशा के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री दिलीप कुमार तिर्की : जी, सर।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह : सर, 2014-15 में ओडिशा के लिए 876.93 करोड़ रुपए का ऐलोकेशन किया गया था जिसमें से अभी तक हमने 684.03 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए हैं। इसका

यूटिलाइजेशन 60.66 करोड़ राज्य सरकार ने कर लिया है। जैसा मैंने कहा कि बहुत से जिलों में जहां पर काम धीमा है या काम नहीं हो रहा है, उन जिलों का भी जो unspent पैसा वहां है, उसके बारे में हमने गाइडलाइन्स जारी की हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि दूसरे जिलों में अगर काम अच्छा हो रहा है, तो उस पैसे को वे वहां खर्च कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

*184 SHRI ANIL DESAI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the progress of construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in various States during the last three years;

(b) whether any financial assistance was received from the World Bank for construction of roads and the target date fixed for completion thereof in any part of the country;

(c) if so, whether the target for construction of roads has been achieved and if so, how many villages have been connected to the nearest big city; and

(d) whether there is any delay in achieving this target and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the report furnished by the State Governments, during the last three years *i.e.* 2011-12,2012-13 and 2013-14, a total road length of 80,472.18 km has been constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). The State wise progress during the last three years is given in the Statement (*See* below).

(b) The Gross Budgetary Support (GBS) for PMGSY programme includes assistance under External Aided Projects by World Bank and Asian Development Bank (ADB). This Ministry has received assistance of US$ 399.5 million for years 2005-2012 under the World Bank supported Rural Roads Projects-I (RRP-I). Further, an assistance of US$ 1400 million has been approved under ongoing Rural Roads Projects-II (RRP-II) for a 5 year period (2011-2015), in 8 participating States namely Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh. The scheduled completion of RRP-II is in November, 2015.